

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18/2019

अपीलार्थी—

1. चुन्नीलाल पुत्र किस्तुरजी
2. जोगसिंह पुत्र किस्तुरजी
3. रूपसिंह पुत्र किस्तुरजी
जाति पुरोहित निवासी सिलोर
तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता—

तहसीलदार समदड़ी जिला
बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2019 जो प्रकरण सं. 01/2019 मे तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण सं. 01/2019 सरकार बनाम चुन्नीलाल व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का सिलोर द्वारा तहसीलदार समदड़ी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिलोर के खसरा नम्बर 365 रकबा 14-04 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि मे से 00-15 बीघा भूमि पर गैर सायल चुन्नीलाल व अन्य द्वारा बाड़ा मय पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91




जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल बावजूद नोटिस तामील दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से तहसीलदार समदड़ी द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 18.02.2019 के द्वारा 1000/- रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 06.03.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन-फानन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी बताते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है वह अपीलांट का कोई नया कब्जा नहीं किया हुआ है बल्कि उक्त भूमि पर पीढियों से लगातार काबिज है तथा अपीलांट के पक्के रहवासी मकानात बने हुए हैं। इसी खसरे की भूमि पर गांव के कई अन्य व्यक्तियों के पक्के व कच्चे मकान आदि बने हुए हैं जिनमें सभी का




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

अपने-अपने परिवार सहित रहवास हैं। इससे पूर्व में अपीलांट्स को धारा 91 के नोटिस दिनांक 02.12.2005, 19.01.2006 दिये गये हैं उसमें खसरा नम्बर 372 गै0मु0 नाडी पर अतिक्रमण होना मानकर दिये हैं और अब अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर 365 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर होना मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट्स का कब्जा आबादी में है अथवा सरकारी गैर मुमकीन नाडी या रास्ता की भूमि पर है। इसके अभाव में अपीलाधीन कार्यवाही आनन-फानन में की गई है जिसे अपास्त किया जाना न्याय संगत है।

6. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में उसे ग्राम बामसीन के खसरा नम्बर 365 कृषि भूमि/सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा मय पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है जबकि अपीलाधीन आदेश में ग्राम सिलोर के खसरा नम्बर 365 में अतिक्रमण मानते हुए बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन कार्यवाही में जारी नोटिस केवल एक पक्षकार को तामील हुआ था अवशेष गैर सायलान के नोटिस तामिन नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय तौर पर जारी कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लिये गये तथा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है।

रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम सिलोर के खसरा नम्बर 365 रकबा 14-04 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि में से 00-15 बीघा भूमि पर बाड़ा मय पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर





जिला कलक्टर
बाइमेर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वयं अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही इस अपील में भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य-सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

8. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम सिलोर में अपना पीढियों का रहवास एवं कब्जा-अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा यह भी प्रकट किया कि उनके अलावा गांव के कई अन्य व्यक्तियों के भी आस-पास में कच्चे-पक्के मकान बने हुए हैं जिनमें वे रहवास करते आ रहे हैं। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया है कि अपीलांट के इसी रहवासीय मकान के लिये पूर्व में इसे गैर मुमकीन नाडी की भूमि मानते हुए अतिक्रमण के नोटिस जारी किये गये थे। इस प्रकार मौके की वस्तुस्थिति ही स्पष्ट नहीं हो रही है कि अपीलांट्स का रहवासीय मकान आबादी की भूमि में है अथवा सरकारी भूमि में है। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्पन्न कार्यवाही का प्रश्न है तो अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ग्राम बामसीन अंकित किया है, तथा प्रकरण सं. 01/2019 पर दर्ज किया गया है जबकि निर्णय की तारीख 18.02.2018 अंकित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आनन-फानन में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये विवादित सरकारी भूमि पर अपीलांट के आधिपत्य बाबत भौतिक स्थिति पर भी कोई विवेचन नहीं किया है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा





जिला न्यायालय
बाड़मेर

मौके कब्जे की विस्तृत जांच एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत के विरुद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांत को जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

10. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विश्राम शीणा)
जिला कलकटर, बाड़मेर
जिला कलकटर
बाड़मेर